year. Will the Government consider manufacturing commercial vehicles in that unit?

MR. SPEAKER. It does not arise.

जालौर तथा सिरोही जिलों (राजस्थान) में उद्योगों की स्थापना

*441. श्री लवावरदा राम फुलिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के पिछड़े जिलों, जालौर तथा सिरोही में बड़ा उद्योग स्थापित करने की भारत सरकार की कोई योजना है;

(ख) क्या यह सच है कि इन जिलों में विभिन्न खनिज आदि प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं तथा उद्योग इन खनिजों पर आधारित होगा;

(ग) यदि हां, तो वहां उद्योग कब तक स्थापित होने की संभावना है; और

(घ) यदि इन क्षेत्रों के लिए ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है तो औद्योगिक दृष्टि से इन पिछड़े क्षेत्रों के लिए, जहां खनिज सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, सरकार द्वारा कोई योजना न बनाये जाने के क्या कारण हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) to (d), At present, the Government of India have no scheme for setting up any big industries in Jalor and Sirohi backward districts in Rajasthan. The State Government and Hindustan Copper Limited are, however, making detailed investigations in order to examine the feasibility of commercial exploitation of the ore reserves of Sirohi and Jalor Districts.

श्री विरदा राम फुलवारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि जालौर में ग्रेनाइट का बहुत बड़ा भण्डार है। सिरोही में भी ये पत्थर मिलते हैं। ये बहुत पिछड़े हुए जिले हैं और वहां के लोगों की यह मांग है कि जालौर में एक बड़ी फैक्टरी लगाई जाए। उन लोगों का यह कहना है कि अगर फैक्टरी नहीं लगाई जाती है, तो वे 1 तारीख से आन्दोलन करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस तरह की एक फैक्टरी जालौर में लगाएंगे क्योंकि वहां की जनता की यह मांग है और वह पिछड़ा हुआ जिला है।

अध्यक्ष महोदय : सवाल पूछिए।

श्री विरदा राम फुलवारिया : जालौर में इसकी बहुत बड़ी फैक्टरी लगाये जाने के लिए वहां की जनता आन्दोलन करेगी तो इसके लिए मंत्री जी का क्या जवाब है ?

SHRI CHARANJIT CHANANA: I wish *Andolan* could create factories. Unfortunately, the factories are set up on the basis of feasibility study. I have told the hon. Member the feasibility studies are being conducted by the Rajasthan State Mineral Development Corporation, because they have the people connected with this.

श्री विरदा राम फुलवारिया : इन जिलों में ग्रेनाइट आदि खनिजों की पर्याप्त मात्रा है और उन पर आधारित वहां उद्योग लगना जरूरी है। क्या सरकार इन जिलों में उद्योग लगायेगी ?

SHRI CHARANJIT CHANANA: For the cement industry feasibility study is already done. The applications for these districts are under consideration. After proper consideration and analysis they would come to a result on the setting up of cement factories in this area.

श्री राम सिंह यादव : जालौर और सिरोही जिलों में ग्रेनाइट बहुतायत में मिलता है। आपने क्या सर्वे करा कर वहां इसकी फीजेबिल्टी के बारे में पता लगाया है और एग्जामिन किया है कि वहां पर उद्योगों को लगाया जा सकता

है या नहीं ? यदि नहीं तो क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

SHRI CHARANJIT CHANANA: I have just now informed the hon. Members that the State Mineral Development Corporation is conducting a feasibility survey into the utilisation of the mineral resources of the State, including granite. As soon as the State Government finalise the feasibility studies, then they would think of setting up plants. I may state for the information of the House that since Rajasthan has industrially backward areas, we are having a meeting in Jaipur on the 3rd and 4th to consider this question.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब देने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि यह मेरा आरोप है कि आज के लिए मैंने 9 क्वेश्चन दिए थे और उन 9 में से सब से अनइम्पार्टेंट क्वश्चन को लाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको मैंने जवाब दे दिया है ।

श्री राम विलास पासवान : **

MR. SPEAKER: Not allowed.

श्री राम विलास पासवान :**

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान

*443. श्री राम विलास पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को 1 नवम्बर, 1973 से 31 जनवरी, 1978 तक की अवधि के लिए बढ़ी हुई दर से मकान किराया भत्ते का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आसूचना ब्यूरो के कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान कर दिया गया है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c). The whole question of the date from and rate at which house rent allowance is admissible is under consideration.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं और जो मेरे सेन्टीमेंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए । मेरे जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे वे इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे । मैंने जो क्वेश्चन किया था उसके फर्स्ट पार्ट का तो जवाब दिया ही नहीं गया है । मेरे प्रश्न का भाग (क) है—

"क्या दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को 1 नवंबर, 1973 से 31 जनवरी, 1978 तक की अवधि के लिए बढ़ी हुई दर से मकान किराया भत्ते का अभी भुगतान किया गया है या नहीं ।"

आपने कह दिया कि उसका हम पता लगा रहे हैं कि किस डेट से दिया जाए ।

मेरा थर्ड क्वेश्चन था कि—

"क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आसूचना ब्यूरो के कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान कर दिया गया है ।"

उसका आपने कहीं जवाब ही नहीं दिया है । तो इसका पहले जवाब दे दें तब न पूरक शुरू करूं ।

**Not recorded.